मुख्यमंत्री भजनलाल ने राधा-कृष्ण शिला का पूजन किया

उन्होंने कहा कि जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन मंदिर, संस्कार, शास्त्र व संस्कृति का केन्द्र बनेगा

जयपुर, 10 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा-कृष्ण शिला का विधिवत पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर भक्ति एवं आध्यात्मिक चेतना के साथ ही सनातन संस्कार, शास्त्र और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का केन्द्र बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण और भगवान शिव के ब्रज आगमन से जुड़े पौराणिक प्रसंग को साझा किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भक्ति, सेवा एवं करुणा के साथ सकारात्मक जीवन जीने तथा मानव कल्याण का मार्ग दिखाती है। हम सभी को इसी मार्ग पर अग्रसर होते हुए समाज और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया तथा गुप्त वृंदावन धाम द्वारा किये जा रहे धार्मिक, सामाजिक व सेवा कार्यों की सराहना की।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा-कृष्ण शिला का विधिवत पूजन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया। साथ ही, गुप्त वृन्दावन धाम द्वारा किए जा रहे धार्मिक, सामाजिक और सेवा कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर विधायक कैलाश वर्मा, गुप्त वृन्दावन धाम के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे।

एक बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभिवादन किया। राहुल ने वरुण की बेटी से भी मुलाकात की थी। प्रियंका के साथ व्यक्तिगत या फोन पर संपर्क की खबरें अथवा अटकलें समय-समय पर सामने आती रही हैं, जिनमें 2026 की शुरुआत के दावे भी शामिल हैं। हालांकि, विस्तृत और सत्यापित राजनीतिक मुलाकातों के प्रमाण बहुत कम हैं। वैचारिक मतभेदों के बावजूद चचेरे भाई-बहनों के बीच सामान्य और सौहार्दपूर्ण व्यक्तिगत संबंध बने हुए हैं। गांधी परिवार के इन चचेरे भाई-बहनों का एक साथ आना भले ही राजनीतिक तस्वीर के लिहाज से आकर्षक हो, लेकिन वास्तविक राजनीति की चुनौतियां बड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी भी संगठनात्मक रूप से कमजोर है और उसका मुख्य फोकस अपनी प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन संबंधी बातचीत पर है। वरुण को कांग्रेस में शामिल करने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की स्थिति बदल सकती है या नेतृत्व और राजनीतिक छवि को लेकर दोनों दलों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। वरुण की मां मेनका गांधी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं को बार-बार खारिज कर चुकी हैं और भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दोहराती रही हैं। ऐसे में वरुण के ऐसे किसी भी कदम का विरोध उनकी ओर से हो सकता है, और यह भी संभव है कि मेनका गांधी स्वयं भाजपा के साथ ही बनी रहें।

'जर्जर हो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आहत न हों या उनकी जान को खतरा न हो। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए और साथ ही प्रशासन की अनदेखी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पक्षकारों ने तुरंत प्रभाव से जवाब पेश नहीं किया तो कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही होगी। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24अगस्त तय की है। अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों को इस मामले में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया है। अदालत के समक्ष यह मामला तब उजागर हुआ, जब आईआईटी, बॉम्बे के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट की इमारत पर बना गुम्बद किसी भी समय गिर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पूर्व में भी कई बार इसी गुम्बद की छत से मलबा गिरा है, जो जजों के चैम्बरों के पास ही है। आईआईटी, जोधपुर की एक्सपर्ट कमेटी ने 19 अप्रेल 2023 को इस मामले पर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें लिखा था कि जर्जर होने के कारण गुम्बद के कई बड़े हिस्से गिर चुके हैं और इसकी मरम्मत की सख्त आवश्यकता है।

ट्रंप ईरान वॉर से सम्मानजनक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को खारिज करने से ऐसा युद्ध लंबा खिंच सकता है, जिसकी आर्थिक और भू-राजनीतिक कीमत पहले ही बढ़ रही है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दबाव का अहम केन्द्र बनकर उभरा है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला यह संकरा जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक है। यहां से दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा की आपूर्ति होती है। लंबे समय तक इसमें रुकावट आने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, परिवहन और बीमा की लागत बढ़ सकती है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

भारत के लिए इसके परिणाम खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है। होर्मुज़ के आसपास लंबे समय तक किसी भी तरह की रुकावट रहने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है, चालू खाते (करंट अकाउन्ट) पर दबाव बढ़ सकता है और देश में ईंधन तथा परिवहन की लागत बढ़ सकती है। अगर जहाजों को लंबे रास्तों से जाना पड़ा या उन्हें ज्यादा सुरक्षा जोखिमों के बीच काम करना पड़ा, तो भारतीय तेल रिफाइनरियों और शिपिंग कंपनियों को भी अधिक माल ढुलाई और बीमा खर्च का सामना करना पड़ेगा।

तथापि, वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक पहलू भी आर्थिक पहलू जितना ही अहम होता जा रहा है। ट्रंप के पास इस बात का मजबूत कारण है कि वे इस टकराव को एक कभी खत्म न होने वाली सैन्य लड़ाई में बदलने से रोकें। लंबा युद्ध उनके मजबूत अमेरिकी नेतृत्व वाले राजनीतिक संदेश को कमजोर कर सकता है। वहीं, तेहरान के लिए बहुत अनुकूल माने जाने वाला समझौता रणनीतिक जीत के उनके दावे को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए वाइट हाउस को ऐसे समझौते की जरूरत है, जिससे कोई साफ दिखाई देने वाला परिणाम मिले, और ट्रंप को ईरान की बड़ी मांगों को मानने की जरूरत भी न पड़े। एक संभावित रास्ता अंतरिम समझौता हो सकता है। इसके तहत ईरान होर्मुज़ से जहाजों के सुरक्षित गुजरने की गारंटी दे सकता है, जबकि अमेरिका सबसे विवादित मुद्दों, जिनमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती शामिल हैं, पर बाद की बातचीत तक फैसला टाल सकता है। ऐसा समझौता दोनों पक्षों को यह दावा करने का मौका दे सकता है कि उनके मूल हितों की रक्षा हुई है।

लेकिन तेहरान के कड़े होते रुख से संकेत मिलता है कि ईरान को लगता है कि उसके पास काफी दबाव बनाने की ताकत है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस जलमार्ग को नियंत्रित करके या इसमें रुकावट डालने की धमकी देकर ईरान न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगियों और एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर भी दबाव डाल सकता है।

इससे होर्मुज़ सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य से कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। यह वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बड़े संघर्ष में मोलभाव का एक ज़रिया बन गया है।

जब तक वॉशिंगटन और तेहरान ऊर्जा की आपूर्ति तुरंत बहाल करने की जरूरत को अपने गहरे रणनीतिक विवादों से अलग करने का कोई रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक यह संघर्ष उस बिंदु से कहीं आगे तक खिंच सकता है, जहाँ वाइट हाउस जीत की घोषणा करने की उम्मीद कर रहा था।

ईरान की कूटनीति में कट्टरपंथियों का दबदबा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन सभी मांगों के बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों पर किसी भी तरह की रियायत नहीं देने का अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। नया समझौता उस अंतरिम समझौते से भी कहीं अधिक कठिन होगा, जिस पर पहले काम किया गया था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जहाजों की आवाजाही में रुकावट अनिश्चित समय तक जारी रहने वाली है। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत "लो-की", यानी बहुत सीमित स्तर पर चल रही है। इससे संकेत मिलता है कि तुरंत कोई रियायत या समझौता होने की संभावना नहीं है। इन बातचीत में अमेरिकियों के गैर-पेशेवर रवैये के मुकाबले ईरानी निश्चित रूप से बढ़त बनाए हुए हैं। अमेरिकी बातचीत करने वाली टीम का नेतृत्व कोई और नहीं, बल्कि डॉनल्ड ट्रंप के मित्र स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर कर रहे थे। खबरों के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ गलतियाँ कीं। डॉनल्ड ट्रंप के दो प्रस्ताव, कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य को मौजूदा युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति में वापस लाया जाए, अब बहुत पीछे छूट गए है और ऐसा लगता है कि ईरान ने पहले ही अपना रुख पक्का कर लिया है कि होर्मुज़ उसके नियंत्रण में रहेगा। दूसरा, ट्रंप का यह दावा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बराक ओबामा के नेतृत्व में हुए बहुराष्ट्रीय जेसीपीओए समझौते से कहीं बेहतर समझौता कर सकते हैं, अब जमीनी हकीकत से पूरी तरह अलग दिख रहा है।

ट्रंप के बार-बार किए गए दावों के बावजूद, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह जीवित हैं और उसके कई परमाणु केन्द्र अब भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ईरान अब अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वह यह संदेश दे रहा है कि अमेरिका क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। ईरान अमेरिका के मध्य पूर्वी सहयोगी देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है और आपसी सुरक्षा के लिए हुए मक्का समझौते की प्रशंसा करते हुए इसे मुसलमानों (सुन्नी) की पहल बता रहा है। साथ ही, ईरान इस समझौते की वास्तविक ताकत को परख रहा है। इसके लिए वह क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम देश सऊदी अरब पर अपने सहयोगी गुटों के हमले बढ़ा रहा है। ईरान समर्थित हूती लड़ाके यमन में सऊदी ठिकानों और क्षेत्र के उसके सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पर सीधे हमले कर रहे हैं। हूती सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर भी हमले कर रहे हैं। अभी तक आपसी सुरक्षा का नया समझौता लागू नहीं हुआ है और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खतरनाक हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। ईरान जल्द ही मक्का समझौते की परीक्षा लेगा, हालांकि भले ही वह सार्वजनिक रूप से इस कदम की तारीफ करता दिख रहा है। हो सकता है कि तनाव कम होने के बजाय, जैसा कि अमेरिकी चाहते हैं, तनाव और बढ़ जाए।

उच्चतम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जनसंवाद में शामिल होने के लिये अलग-अलग जिलों से आमजन,पर्यावरणप्रेमी और खनन व्यवसाय से जुड़े उद्यमी आए। जितने लोग सभागार के अंदर थे, उससे ज्यादा लोग बाहर लगे टेंट के नीचे बैठे थे। कई लोग सभागार के पोर्च में खड़े थे, जगह ही कम पड़ गई थी। यह बैठक सुबह 10 से 12 बजे तक चली।

शरद पवार की पार्टी परिसीमन बिल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं कि इंडिया गठबंधन का यह सहयोगी दल संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर सरकार का समर्थन कर सकता है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक करीब आधे घंटे तक चली। सांसदों ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति और सिंचाई से जुड़े मुद्दों के अलावा, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं भी प्रधानमंत्री के सामने रखीं।

प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहीर अन्ना भाऊ साठे और तुकडोजी महाराज को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। सूत्रों ने बताया कि सांसदों ने नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री डी. वाई. पाटिल के नाम पर रखने की मांग भी की। सांसदों ने अपनी मांगों और चिंताओं को लेकर प्रधानमंत्री को एक लिखित ज्ञापन सौंपा और बैठक को सकारात्मक बताया। सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देने योग्य हैं और उन्होंने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन मीटिंग में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक और विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एसीआरए) पर चर्चा नहीं हुई। सांसदों ने कहा है कि वे एफसीआरए विधेयक का विरोध करेंगे।

बैठक से पहले सुले ने कहा था कि सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय इसलिए मांगा था, क्योंकि महाराष्ट्र में सहायता के लिए उन्हें धनराशि नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था, जहां तक परिसीमन विधेयक का सवाल है, इसे अभी पेश ही नहीं किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जब विधेयक आएगा, तो ऑल इंडिया अलायंस में इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर विधेयक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया जाता है और यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि इस विस्तार को किस तरह लागू किया जाएगा, तो एनसीपी (एसपी) विधेयक का समर्थन करेगी। यह बैठक एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच संभावित सुलह की अटकलों के फिर तेज होने के बीच हुई है। दोनों गुटों के नेताओं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के बीच हुई मुलाकातों की खबरों के बाद इन अटकलों को और बल मिला है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908